इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष: एक समग्र विश्लेषण

संदर्भ:

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में 60 दिनों के युद्धविराम का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य बंधकों की रिहाई को सुगम बनाना और शांति वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। यह कदम इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के साथ उठाया गया है।

परिचय:

- इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय विवादों में से एक है। यह संघर्ष प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादों, ऐतिहासिक शिकायतों, धार्मिक महत्व, और क्षेत्रीय दावों से चिह्नित है। यह संघर्ष एक सदी से अधिक समय से चल रहा है और इसने युद्धों, उथल-पुथल, कूटनीतिक प्रयासों, और मानवतावादी संकटों को जन्म दिया है। इस संघर्ष को समझने के लिए इसके गहरे ऐतिहासिक कारणों और वर्तमान संघर्षों को देखना आवश्यक है, जो मध्य पूर्व को आकार दे रहे हैं।
- संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ें: 19वीं सदी से 20वीं सदी के प्रारंभ तक

यहूदी राष्ट्रवाद और बाल्फ़ोर घोषणा (1917):

- 19वीं सदी के अंत में, यूरोपीय यहूदियों ने, जो उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, उन्होंने यहूदी आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना करना था। यह आंदोलन यूरोप में बढ़ते एंटी-सेमिटिज़म द्वारा प्रेरित था और यह तेजी से लोकप्रिय हुआ।

- ब्रिटिश सरकार द्वारा 1917 में की गई बाल्फ़ोर घोषणा ने फिलिस्तीन में "यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर" की स्थापना का समर्थन किया। हालांकि, इसने फिलिस्तीन के मौजूदा अरब समुदायों के अधिकारों को भी स्वीकार किया था।

ब्रिटिश जनादेश और अरब राष्ट्रवाद :

- प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर शासन करने का जनादेश दिया, जहाँ यहूदी आव्रजन बढ़ा और स्थानीय अरब जनसंख्या और यहूदी बसने वालों के बीच तनाव बढ़ा।
- अरब राष्ट्रवाद पश्चिमी उपनिवेशवाद और ज़ायनिज़्म के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप उभरी, जिससे यहूदी आव्रजन के खिलाफ बढ़ती हुई विरोधाभासी भावनाएँ उत्पन्न हुई।

इज़राइल की स्थापना और पहला अरब-इज़राइली युद्ध

संयुक्त राष्ट्र का विभाजन योजना (1947):

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में एक विभाजन योजना प्रस्तावित की, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करना था, जिसमें यरूशलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव था। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, और भूमि को विभाजित करने से इनकार किया।

इज़राइल राज्य की घोषणा (1948):

- 14 मई 1948 को डेविड बेन-गुरियन ने इज़राइल राज्य की घोषणा की। इसने आस-पास के अरब देशों से तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप पहला अरब-इज़राइली युद्ध (1948-1949) हुआ।
- इज़राइल की विजय: प्रारंभिक विफलताओं के बावजूद, इज़राइल ने अपनी क्षेत्रीय रक्षा की और युद्ध के अंत तक, उसने संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के तहत आवंटित क्षेत्र से अधिक भूमि पर नियंत्रण कर लिया। लाखों फिलिस्तीनी अरब विस्थापित हो गए, जिससे फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ।
- 1967 का छह दिन युद्ध और फिलिस्तीनी क्षेत्रों का अधिग्रहण

युद्ध पूर्व तनाव:

- 1960 के दशक में इज़राइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ गया, जो जून 1967 में छह दिन युद्ध में परिणत हुआ। इज़राइल ने, संभावित हमले का डर महसूस करते हुए, मिस्र, सीरिया और जॉर्डन पर एक पूर्वव्यापी हमला किया।

• क्षेत्रीय विस्तार:

- इज़राइल की क्षेत्रीय बढ़ोत्तरी में पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलम, गाजा पट्टी, और गोलान हाइट्स शामिल थे। ये क्षेत्र भविष्य के संघर्षों और वार्ताओं का केंद्र बिंदु बन गए।
- पश्चिमी तट और गाजा में इज़राइल का कब्जा फिलिस्तीनी जनसंख्या पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे नाराजगी और हिंसा और बढ़ी।

फिलिस्तीनी प्रतिरोध का उदय: पीएलओ और इंटिफ़ादा

फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) का गठन:

- 1964 में, पीएलओ का गठन फिलिस्तीन को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मुक्त करने के उद्देश्य से किया गया था। पीएलओ का सशस्त्र विंग, फतह, जिसका नेतृत्व यासिर अराफात ने किया, फिलिस्तीनी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया।

पहली इंटिफ़ादा (1987-1993):

- कब्जे वाले क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ती हुई निराशा ने पहली इंटिफ़ादा का जन्म लिया, जो इज़राइल के कब्जे के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह था। इसे व्यापक विरोधों, नागरिक अवज्ञा, और हिंसक टकरावों के रूप में देखा गया।

दूसरी इंटिफ़ादा (2000-2005):

- शांति वार्ताओं की विफलता और इज़राइल द्वारा बसावट के विस्तार ने 2000 में दूसरी इंटिफ़ादा को जन्म दिया। इस विद्रोह में अत्यधिक हिंसा, आत्मघाती बम विस्फोट, और सैन्य अभियानों का सामना किया गया।

शांति प्रयास: ओस्लो समझौते और दो-राज्य समाधान की दिशा

ओस्लो समझौते (1993):

- ओस्लो समझौते इज़राइल और पीएलओ के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता था, जिसे अमेरिका के समर्थन से अंजाम दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पारस्परिक पहचान और पश्चिमी तट और गाजा में सीमित स्व-शासन के साथ फिलिस्तीनी प्राधिकरण का गठन हुआ। हालांकि, यरूशलम की स्थिति, शरणार्थी और सीमाओं जैसे मुख्य मुद्दे हल नहीं हो सके।

कैंप डेविड शिखर सम्मेलन (2000):

- 2000 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में शांति समझौते को अंतिम रूप देने में असफलता ने अविश्वास को और गहरा किया। इसके बाद की दूसरी इंटिफ़ादा ने हिंसा की वापसी की और शांति वार्ताओं को वर्षों तक रोक दिया।

हामास, गाजा, और जारी संघर्ष

हामास का सत्ता में आना:

- 2006 में, हामास संगठन, जो एक इस्लामिक उग्रवादी समूह है, ने फिलिस्तीनी legislative चुनावों में जीत हासिल की और फतह के साथ हिंसक संघर्ष के बाद गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। इस विभाजन ने दो अलग-अलग फिलिस्तीनी प्राधिकरणों का निर्माण किया: गाजा में हामास और पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA)।

गाजा का इज़राइली नाकाबंदी:

- इज़राइल ने गाजा पर एक सख्त नाकाबंदी लागू की, यह कहते हुए कि यह हामास के रॉकेट हमलों के कारण सुरक्षा चिंताओं से संबंधित है। इस नाकाबंदी ने गाजा के लोगों के लिए गंभीर मानवतावादी संकट पैदा किया, और यह हिंसा की आवधिक पुनरावृत्तियों का कारण बनी।

गाजा युद्ध (2008-आज तक):

- इज़राइल ने हामास द्वारा रॉकेट हमलों के जवाब में कई सैन्य अभियान चलाए, जिनमें ऑपरेशन कास्ट लीड (2008), ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज (2014), और ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल्स (2021) शामिल हैं। इन अभियानों के परिणामस्वरूप गाजा में भारी नागरिक हताहत हुए और व्यापक तबाही हुई।

वर्तमान संकट: हामास हमला (2023)

2023 संघर्ष की उत्पत्ति:

- अक्टूबर 2023 में संघर्ष फिर से उभरा, जब हामास ने इज़राइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसका कारण इज़राइल की पश्चिमी तट पर की गई कार्रवाइयाँ और यरूशलम में अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी उपासकों पर हमले थे।

हताहत और मानवतावादी प्रभाव:

- हमास की मिसाइल बौछार और इज़राइल की प्रतिशोधात्मक हवाई हमलों में दोनों पक्षों पर हजारों हताहत हुए, जिसमें गाजा ने विनाश का प्रमुख बोझ उठाया। मानवतावादी संकट और बढ़ता जा रहा है, जिसमें व्यापक विस्थापन और बुनियादी सेवाओं की कमी देखी जा रही है।

क्षेत्रीय प्रभाव:

- यह संघर्ष व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता का जोखिम उत्पन्न करता है, जिसमें लेबनान से हिजबुल्लाह की भागीदारी और इज़राइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने वाले अब्राहम समझौतों के पतन की आशंका है।

भारत की स्थिति संघर्ष पर

फिलिस्तीन के लिए ऐतिहासिक समर्थन:

- भारत ने लंबे समय तक फिलिस्तीनी कारण का समर्थन किया है, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ इसकी ऐतिहासिक स्थिति और अरब देशों के साथ इसके संबंधों को दर्शाता है। हालांकि, भारत ने 1992 में इज़राइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, जिससे उसकी विदेश नीति में एक बदलाव आया।

संतुलित कूटनीति:

- भारत दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है और एक तटस्थ रुख बनाए रखता है, जो संवाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राथमिकता देता है। भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता प्रदान की है और साथ ही इज़राइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, विशेष रूप से रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में।

भारत के लिए चुनौतियाँ और प्रभाव:

- भारत की संतुलित दृष्टिकोण अब और अधिक चुनौतीपूर्ण हो रही है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा, इज़राइल के साथ रक्षा संबंधों, और मध्य पूर्व में व्यापक अस्थिरता के प्रभावों के संदर्भ में।

आगे का रास्ता: संभावित समाधान

- दो-राज्य समाधान: यह सबसे अधिक समर्थन प्राप्त समाधान है, हालांकि यह हिंसा, बसावट के विस्तार, और यरूशलम की स्थिति के कारण चुनौतीपूर्ण है।
- एक-राज्य समाधान: यह एक और विवादास्पद विकल्प है जिसमें यहूदी और फिलिस्तीनी समान अधिकारों को साझा करते हैं, हालांकि यह राष्ट्रीय पहचान पर सवाल उठाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय भूमिका: अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में वृद्धि, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और क्षेत्रीय शक्तियाँ शामिल हों, दोनों पक्षों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने और संवाद को बढ़ावा देने के लिए।

- आर्थिक और मानवीय सहायता: दोनों पक्षों को आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना होगा, विशेष रूप से गाजा में, ताकि एक स्थायी शांति को बढ़ावा दिया जा सके।
- सुरक्षा गारंटी: सीमा की निगरानी करने, मिलिशिया को निरस्त्र करने और आगे के बढ़ते तनाव को रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय शांति सैन्य बलों की स्थापना।

निष्कर्ष

- इज़राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष आधुनिक भू-राजनीति में सबसे गहरे विवादों में से एक है। यह धार्मिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक जटिलताओं में निहित है, और इसका समाधान अभी भी दूर है। जबकि दो-राज्य समाधान सबसे व्यवहारिक रास्ता है, एक स्थायी शांति के लिए साहसी नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और न्याय, सुरक्षा और आपसी पहचान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। भारत का इस जटिल मुद्दे को सुलझाने में भूमिका, जिसमें अपने रणनीतिक हितों और फिलिस्तीनी कारण के प्रति ऐतिहासिक समर्थन को संतुलित करना होगा, क्षेत्र में एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण रहेगा।